भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 740

जिसका उत्तर 04.12.2025 को दिया जाना है

तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण

740. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-45 (एनएच-45), राष्ट्रीय राजमार्ग-32 (एनएच-32) और राष्ट्रीय राजमार्ग-44 (एनएच-44) सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के कई खंडों के खराब अनुरक्षण और बिगड़ती स्थिति की जानकारी है;

(ख) तमिलनाडु राज्य में वर्तमान में मरम्मत किए जा रहे या अनुरक्षण के लिए लंबित राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है;

(ग) तमिलनाडु राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग अनुरक्षण के लिए आवंटित की गई और उपयोग की गई निधि कितनी है;

(घ) क्या सरकार का इन राजमार्गों के निरीक्षण और गुणवत्ता संपरीक्षा की आवृत्ति बढ़ाने का विचार है; और

(ङ) समयबद्ध अनुरक्षण, गुणवत्तापूर्ण सामग्री के उपयोग और ठेकेदारों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख): तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सहित राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत प्रक्रिया है। सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग-45, राष्ट्रीय राजमार्ग-32 और राष्ट्रीय राजमार्ग-44 सहित तमिलनाडु राज्य में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) खंडों की स्थिति की जानकारी है। सरकार ने मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) नेटवर्क के रखरखाव को प्राथमिकता दी है और अन्य बातों के साथ-साथ जवाबदेह रखरखाव एजेंसी के माध्यम से सभी एनएच खंडों के रखरखाव और मरम्मत (एम एंड आर) सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित किया है। सरकार की योजना है कि तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के सभी एनएच खंड का रखरखाव निम्नलिखित में से एक तंत्र के माध्यम से होने चाहिए:

i. राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों, जहां विकास कार्य शुरू हो गए हैं या संचालन, रखरखाव और हस्तांतरण (ओएमटी) रियायतें/संचालन और रखरखाव (ओएंडएम) अनुबंध सौंप दिए गए हैं, का रखरखाव और

मरम्मत (एम एंड आर), दोष देयता अवधि (डीएलपी)/रियायत अवधि के अंत तक संबंधित रियायतग्राहियों/ठेकेदारों की जिम्मेदारी है। इसी तरह, टीओटी (टोल संचालन और हस्तांतरण) और इनविट (अवसंरचना निवेश न्यास) के अंतर्गत एनएच खंडों के लिए, एम एंड आर की जिम्मेदारी रियायत अवधि के अंत तक संबंधित रियायतग्राही की है।

ii. राष्ट्रीय राजमार्गों के शेष सभी खंडों के लिए, सरकार ने निष्पादन-आधारित रखरखाव अनुबंध (पीबीएमसी) या अल्पकालिक रखरखाव अनुबंध (एसटीएमसी) के माध्यम से रखरखाव कार्य करने का नीतिगत निर्णय लिया है।

सड़क की दशा में चिह्नित दोषों / समस्याओं की मरम्मत के साथ ही अन्य रखरखाव / मरम्मत कार्य ठेकेदार / रियायतग्राही द्वारा अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर किए जाते हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधियां, उन राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा जो रियायत करारों के अधीन या दोष देयता अवधि के अंतर्गत हैं, जहां उचित रखरखाव सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित रियायतग्राही या ठेकेदार की है और ऐसी लागत तमिलनाडु में परियोजना लागत में शामिल है, इस प्रकार हैं:

वर्ष	आवंटन (करोड़ रु.)	उपयोग (करोड़ रु.)
2022-23	554	554
2023-24	340	340
2024-25	448	439

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों के निरीक्षण और गुणवत्ता निगरानी की एक मजबूत प्रणाली लागू है अर्थात्, तृतीय-पक्ष गुणवत्ता लेखा परीक्षा, स्वतंत्र अभियंता समीक्षा और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा आवधिक निरीक्षण, ताकि निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। यातायात की सुरक्षित और सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए इन निरीक्षणों के निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक रखरखाव कार्य किए जाते हैं।

(ड.) सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें शामिल हैं:

i. परेशानी मुक्त सड़क सुनिश्चित करने के लिए निष्पादन-आधारित रखरखाव अनुबंध (पीबीएमसी) और अल्पकालिक रखरखाव अनुबंध (एसटीएमसी) को अपनाना।

ii. तृतीय-पक्ष गुणवत्ता लेखा परीक्षकों की तैनाती सहित गुणवत्ता नियंत्रण मानदंडों को कड़ाई से लागू करना।

iii. परियोजनाओं के पर्यवेक्षण के लिए तैनात प्राधिकरण इंजीनियर/स्वतंत्र अभियंता सहित फील्ड अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण के माध्यम से सड़क की स्थिति में चिह्नित दोषों/मुद्दों की मरम्मत के साथ ही अन्य रखरखाव/मरम्मत कार्य सुनिश्चित किए जाते हैं। डीएलपी/रियायत अवधि के दौरान गैर-अनुपालन के लिए, अनुबंध शर्तों के अनुसार जुर्माना लगाया जाता है या डीएलपी अवधि बढ़ाई जाती है। दंड प्रावधानों में देय भुगतान में कटौती, क्षति वसूली, प्रतिबंध लगाना/ब्लैक लिस्ट करना आदि शामिल हैं।

iv. रखरखाव कार्यों के लिए स्पष्ट समय सीमा तय करना और डेटा लेक पोर्टल और समीक्षा बैठकों के माध्यम से करीबी निगरानी करना।

v. सभी रखरखाव कार्यों के लिए भारतीय सड़क कांग्रेस के विनिर्देशों का अनुपालन करना।

*****